(c) The Government has not taken any decision on this matter so far.

(d) The Railwaymen have demanded payment of 8·33% of wages as minimum bonus.

(e) For railway employees alone the financial implications will be about Rs. 71 crores per annum.

(f) No such proposal has been received by the Government.

Amendment to Bonus Act

*77. SHRI ANANT DAVE:
SHRI DALPAT SINGH PARASTE:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) Whether the recommendations of the Bhoothalingam Committee have been considered and decision taken on an integrated policy of the Government on bonus issue as a whole;

(b) whether Government are contemplating to bring forward the necessary amendments in the Bonus Act framed on the basis of this decision;

(c) if so, what are its details; and

(d) if not, how it will affect the interest of industrial workers as such ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). The question of bonus, including extension of the coverage and related issues, is receiving very careful consideration and the Government's intention is to introduce the necessary legislation before the festival season.

दो-मंजिले रेल डिब्बे

*78. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दो मंजिले रेल डिब्बे बनाने के कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि थोड़ी दूर की रेल यात्रा में यात्रियों को भीड़ अधिक रहती है ; और

(ग) क्या सरकार का दो-मंजिला रेल डिब्बे लगाने के मामले में थोड़ी दूरी की गाड़ियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 1977-78 के दौरान सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा बड़ी लाइन के 12 दो-मंजिले सवारी डिब्बों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और 1979-80 की अवधि में 24 और दो मंजिले सवारी डिब्बों का उत्पादन होने की प्रत्याशा है ।

(ख) जी हां, केवल महत्वपूर्ण स्टेशनों पर और उनके आस पास ।

(ग) अपेक्षाकृत कम धुल वाले थोड़ी दूरी के चुने हुए मार्गों पर दो मंजिले सवारी डिब्बे चलाने का विनिश्चय किया गया है ।

Development of Cochin Port

*79. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision on schemes for the development of the Cochin Harbour submitted by the Port Trust; and

(b) if so, the details of the project and other details thereof ?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) and (b), An integrated scheme for the development of Cochin Port for handling of POL and fertilisers at an estimated cost of Rs. 26·08 crores has been received from Cochin Port Trust for sanction by the Government. A decision would be taken on merits of the proposal.

पंजाब में काम करने वाले बिहार और उड़ीसा के बंधुआ मजदूर

*50. **श्री राम नरेश कुशवाहा :**

श्री राम सागर :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाया था ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान "नवभारत टाइम्स" दिनांक 30 मई, 1979 में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बिहार और उड़ीसा के लगभग 30 कृषि मजदूर जिला जालन्धर में तलवन्डी गांव में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं और उनसे बन्दूक की नोक पर जबरदस्ती काम लिया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अन्य स्थानों का पता लगाने के लिए, जहां पर बंधुआ मजदूर प्रथा अभी भी प्रचलित है, कोई आयोग गठित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या उन मजदूरों को कोई रोजगार दिया गया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) (क) से (घ) बलात या अंशतः बलात श्रम पद्धति को, जिस के अन्तर्गत ऋणी लेनदार के लिये श्रम या सेवा करता है और जो सामान्यतः बंधित श्रम पद्धति के नाम से जानी जाती है, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें इस के उपबन्धों को कार्यान्वित करती हैं तथा जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियां तथा ऐसे कार्य प्रदान करती हैं, जो वह यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें कि अधिनियम के उपबन्धों का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है।

2. समाचारपत्र की रिपोर्ट के अनुसार जिला जालन्धर में बलात श्रम की अभिकथित घटना पंजाब सरकार को भेजी गई थी और अनुरोध किया गया था कि वह बंधित श्रमिकों को मुक्त कराए तथा उन का पुनर्वास करे। पंजाब सरकार से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि पुलिस की मध्यस्थता से अब 36 संबन्धित व्यक्तियों के मजूरी के हिसाब किताब चुकता कर दिए गए, जो अधिकांश रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश तथा कुछ उड़ीसा के प्रवासी श्रमिक थे, और तलवंडी, अबदार ग्राम (जिला जालन्धर) में जमींदार के पास काम कर रहे थे। जांच-पड़ताल जारी है और पंजाब सरकार से आगे और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) अप्रेल, 1979 में बंधित श्रमिक संबंधी एक समिति गठित की गई जो बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने में और अधिक कारबर प्रक्रियाओं और पद्धतियों की समीक्षा करेगी तथा उन में सुधार की सिफारिश करेगी। किसी प्रकार का आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है।

Continuous closure of Gate No. 499

581. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Department has received complaints regarding the inconvenience and obstruction of traffic caused by the almost continuous closing of Gate No. 499 situated in the heart of business area, half a furlong from the Raja Ki Mandi Station;

(b) if so, what action has been or is proposed to be taken thereon; and

(c) whether Government propose to order its electrification, and automatic operation to be taken in hand immediately to obviate this trouble ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) and (c). It is porposed to provide automatic lifting barrier type gates for which approval of Commissioner of Railway Safety (as required under the rules) has already been sought. The work would be taken in hand immediately on receipt of approval from the Commissioner of Railway Safety.

Vehicles in Headquarters of N.E. and Northern Railway

583. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to the Unstarred question No. 8723 on the 26th April, 1979 regarding automobile vehicle of Railways and state:

(a) the number of vehicles existing at the Headquarters and Divisional Headquarters on the N.E. and Northern Railway 10 years back and on date;

(b) the reasons for such enormous increase in number of these vehicles while offices are closely located and the work was managed with lesser number of vehicles earlier; and

(c) whether Government intend to get the necessity of these huge number of vehicles scrutinised and withdraw excess number of vehicles to enforce economy and control their misuse, if not the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(c) Based on the instructions issued by Ministry of Finance on 22-5-79, Ministry of Railways have directed all the Zonal Railways, which includes Northern and N.E. Railways, to undertake a review of the strength of the staff cars and other vehicles, including operational vehicles, with a view to exploring the possibility of reducing the number of vehicles by atleast 10%. Till this review is completed, Ministry of Railways will not consider purchase of any new staff car or replacement of the existing ones.